

कामकाजी महिला

वर्ष 5

अंक 5

जून, 1993

मूल्य : 2 रु०



पंचायत चुनाव प्रचार में हुंगली जिले के बीदीपुर गाँव में महिलाओं की एक सभा का दृश्य

पंजाब में आंगनवाड़ी महिलाओं की नई कमेटी स्थापित

25 अप्रैल को पुरानी कमेटी पुनर्गठन के लिए पंजाब आंगनवाड़ी कमियों तथा सहयोगियों की जनरल बॉडी की बैठक हुई। लगभग सभी जिलों से दो हजार के आस-पास कुशल आंगनवाड़ी कमियों ने इसमें हिस्सा लिया।

जनरल बॉडी तथा नई कमेटी बनाने की पीछे कारण यही था कि संघ की भूतपूर्व प्रधान श्रीमति सुरिन्द्र कौर ने कांग्रेस पार्टी अपना ली है और प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वह कांग्रेस के महिला अरथे की नेता बन गई हैं। उन्होंने संगठन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। रिपोर्ट से यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने विधान के सिद्धांत के विपरीत मुख्य मंत्री श्री बेंत सिंह को 8 मार्च की रैली पर बोलेने के लिए आमंत्रित किया।

यहाँ जनरल बॉडी की बैठक बुलाने तथा नई कमेटी के निर्वाचन के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कार्यालय सेविका कामरेड राजिन्द्र कौर ने नई स्थितियों से उत्पन्न नए संगठन की आवश्यकताओं पर वक्तव्य दिया जिसे विधान के समक्ष रखने पर एक मत से पारित कर दिया गया।

प्रत्येक जिले के कमियों ने नई राजनैतिक स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कमियों के प्रति केन्द्र सरकार के अपनाए रवैये के बारे में भी रोष प्रकट किया। 1986 से यहाँ पारिश्रमिक पर इन्क्रेमेंट नहीं दिया गया। बोट क्लब तथा राज्यों में वर्षों के संघर्ष तथा घरनों के बाद हाल ही में 125 रुपये की वृद्धि हुई है और केन्द्र सरकार द्वारा 90 रुपये भी दिए गये। फंडरेशन की महासचिव कामरेड नलिमा मोएला ने बैठक को प्रारम्भ करते हुए, कार्य करने की बेहतर स्थितियों तथा पारिश्रमिक वृद्धि के लिए सामूहिक रूप से वर्षों से शुरू किए हुए संघर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने

[पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन (सीटू) मध्यप्रदेश

व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन द्वारा कार्यशाला

साईलेंट में फैक्ट्री में लगी आग से 240 महिला उद्यमियों की मृत्यु

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों केन्द्रीकरण के विरुद्ध

मिपुरा के साधियों को हादिक बघाई

इटक के गुंडों द्वारा सीटू मजदूरों की हत्या की सीटू व प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन द्वारा भरसना

कां० क्रिस हानी की हत्या

कर्नाटक राज्य बीड़ी मजदूर फेडरेशन का छठा सम्मेलन

ए.आई.सी.सी.इन्क्यू.इन्क्यू. तमिलनाडु का चौथा राज्य सम्मेलन

प. बंगाल वाम मोर्चा सरकार की पंचायत चुनाव में विशाल सफलता पर हमारी हादिक शुभकामनाएं शबाना आजमी कहती हैं...

प. बंगाल : 1993 के पंचायत चुनाव

बिहार सरकार के पक्षां 1373, आंगनवाड़ी महिलाओं पर जुल्म

महिला उत्पीड़न : अमरीका भी पीछे नहीं

कर्नाटक कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक कामगार महिलाओं के लिए 'कक्षा'

केरल के खादी वस्त्रोद्योग में महिलाएं केवल 5 से 9 रु. पा रही हैं—कामगार महिला समन्वय समिति

नयी आर्थिक नीति और भारत इलेक्ट्रोनिक्स शैक्काओं-सहायिकाओं द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय नोबलपुर पर धरना

मई दिवस पर विद्व भर में महिलाओं का क्रांतिकारी अभिनन्दन

ए.आई.सी.सी.इन्क्यू. ने एकता प्रकट की

आंगनवाड़ी महिलाएं भारत बन्द में शामिल होंगी

विषी में सम्मेलन

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिने की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोप्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, क्षिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन (सीटू) म.प्र.

मानिनी सरोज — ग्वाहेर

मध्य प्रदेश स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की यूनियन के पंजीयन के लिये यद्यपि कार्यवाही जारी है फिर भी व्यावहारिक तौर पर यूनियन का कार्य एक दो स्थानों पर ही किया जा रहा है। आंदोलनात्मक गतिविधियाँ केवल ग्वालियर संभाग में हुई हैं।

ग्वालियर संभाग

सांगठनिक

19 अप्रैल 1992 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका यूनियन का स्थापना सम्मेलन हुआ था जिसमें करीब एक सौ पचास प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में 9 सदस्यीय संचालन समिति व 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। 3 मई 92 को संचालन समिति की पहली बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई।

स्थापना सम्मेलन के बाद सदस्यता में वृद्धि हुई लेकिन अपेक्षा से काफी कम हुई। वर्तमान में 1992 में जो सदस्यता हुई उस आधार पर सदस्यता 125 है। जनवरी से सदस्यता का काम लगभग ठप्प पड़ा है। भविष्य के लिये सदस्यता का लक्ष्य 300 रखा गया है।

ग्वालियर संभाग में परियोजनाएँ

ग्वालियर संभाग के छः जिलों में 15 परियोजना चल रही हैं जिसमें 1922 कार्यकर्ता और इतनी ही सहायिकाएँ कार्यरत हैं इसमें 13 ग्रामीण, शहरी (ग्वालियर) व। आदिवासी क्षेत्र में हैं। हमारी यूनियन का प्रभाव वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्र में है जिसमें 100 कार्यकर्ता व इतनी ही सहायिकाएँ।

आंदोलनात्मक

(1) 22 मई 1992 को एक दिवसीय धरना

कमिश्नरी कार्यालय पर दिया गया जिसमें लगभग 125 महिलाओं ने हिस्सेदारी की। धरना नियमित मानदेय की मांग को लेकर किया गया साथ ही स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी को रोकने की भी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप नियमित रूप से मानदेय मिलने लगा और कई झण्ट अधिकारियों के तबादले हुए।

(2) 7 जून को शिवपुरी में स्थानीय मांगों को लेकर धरना दिया गया।

(3) 16 सितम्बर को अखिल भारतीय आन्दोलन के अनुसार भोपाल में हुए राज्यस्तरीय प्रदर्शन में ग्वालियर से 100 के लगभग कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने शिरकत की।

(4) 25 नवंबर दिल्ली की रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं में से लगभग 90 महिलाएँ ग्वालियर से शरीक हुईं।

6 जनवरी 1993 को साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में जो सीटू की ओर से आयोजित किया गया था पांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

21 जनवरी 1993 को संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया जिसमें 135 महिलाएँ शामिल हुईं। जनवरी के बाद से गतिविधियाँ लगभग बंद हैं।

13 जून 1993 को केन्द्र सरकार की नई आर्थिक नीति के खिलाफ राज्य स्तर के भोपाल सम्मेलन में किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने हिस्सा नहीं लिया।

जून के अन्त में संचालन समिति की एक बैठक तय की गई है जिसमें 10 जुलाई मांग दिवस के कार्यक्रम के बारे में योजना बनाई जाएगी।

भोपाल संभाग

सांगठनिक

भोपाल में शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की अलग-अलग छः-सात बैठकें हुई हैं जिसमें परियोजना के स्तर में पांच या छः सदस्यीय छोटी-छोटी समितियों का गठन किया गया है परन्तु सदस्यता अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है।

भोपाल संभाग में परियोजनाएं

भोपाल संभाग के 7 जिलों में 22 परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें 2999 कार्यकर्ता व इतनी ही सहायिकाएं हैं। इसमें 5 शहरी 11 ग्रामीण व 6 आदिवासी क्षेत्र में हैं। अभी हमारा प्रयास केवल भोपाल के शहरी क्षेत्र तक सीमित है जिसमें 792 कार्यकर्ता व सहायिकाएं (792) हैं।

आंदोलनात्मक

आंदोलनात्मक गतिविधियां भोपाल में नहीं हुई हैं केवल दो बार यूनिशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कमिशनर महिला एवं बाल विकास की स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है।

16 सितम्बर '92 के राज्यस्तरीय प्रदर्शन में भोपाल की 5 कार्यकर्ता ने शिरकत की थी।

25 नवंबर को दिल्ली रैली में व 13 जून '93 को भोपाल के सम्मेलन में किसी कार्यकर्ता ने हिस्सा नहीं लिया।

भविष्य में 10 जुलाई, 1993 को मांग दिवस मनाने के लिए स्थानीय समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के अन्य संभाग

ग्वालियर व भोपाल संभाग के अलावा 8 अन्य संभागों में 138 परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें 21215 कार्यकर्ता व इतनी ही सहायिकाएं कार्यरत हैं।

हमारी कोशिश है कि बस्तर व रीवा संभाग में हमारे जो संपर्क हैं उनके जरिए वहां हमारे संगठन का विस्तार किया जाये।

वर्तमान में छोटे-छोटे संगठनों के रूप में हमारी यूनिशन ग्वालियर संभाग के गुना कराहल में रीवा संभाग के शहडोल में विलासपुर के कोटा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

बड़े हुए मानदेय

अक्टूबर 1992 में बड़े हुए मानदेय के बारे में म.प्र. की रिपोर्ट है कि भोपाल, ग्वालियर में अप्रैल से पिछले एप्रियस के साथ बड़े हुए मानदेय नहीं मिले हैं। अन्य स्थानों के बारे में यह आत नहीं हो पाया है कि वहां पर कार्यकर्ताओं को बड़े हुए मानदेय मिले हैं या नहीं।

कामकाजी महिला

सीटू केन्द्र द्वारा प्रकाशित यह त्रैमासिक केवल ग्वालियर संभाग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच विशेष रूप से बेचा जाता है यहां इसकी 50 प्रतिशत आती है।

हमारी कमजोरियां

मध्यप्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्य-होने के बावजूद हम आज तक उनके बीच अपना प्रभाव कायम नहीं कर पाये हैं।

हमारी सक्रिय कार्यकर्ताओं का आंगनवाड़ी की महिलाओं से लगातार संपर्क नहीं रहता।

हमारे द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या बढ़ाने के उद्देश्य से कोई विशेष कार्यक्रम तय नहीं किये जाते।

सावी योजनाएं

ग्वालियर का अनुभव हमें बताता है कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष रूप से किसी महिला साथी की अनुपस्थिति के बावजूद जहां सीटू प्रभावशाली है। वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच संगठन बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनवादी महिला समिति की मदद ली जा सकती है। इस योजना के तहत इन्दौर में सीटू व बस्तर में ज.म.स. के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संगठन बनाने की योजना है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यशाला

□ हेमलता

श्रम संगठनों में भारतीय महिलाओं के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर आयोजित कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित अनेक कार्यशालाओं में से एक है। यह अपने किस्म की पहली कार्यशाला थी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा श्रमिक सघों की महिलाओं के लिए आयोजित की गयी थी। इस जिस प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग हुआ वह भी पहली बार प्रयोग में लायी गयी थी।

कार्यशाला का उद्देश्य भारत में श्रम संगठनों में कार्यरत महिलाओं को प्रशिक्षण देना था ताकि वे मजदूरों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दे सकें।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सीटू से तीन प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया। सीटू ने प. बंगाल की कामरेड सविता घटर्जी, का. किरण मोणे (महाराष्ट्र) तथा का. आंध्रप्रदेश की का. के. हेमलता को मनोनीत किया। का. सविता व का. हेमलता ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या 13 थी। इनमें से 6 एच.एम.एस. से, चार इंटक से, दो सीटू से तथा एक एन.एल.ओ. से थीं।

कार्यशाला का आयोजन आई.एल.ओ. जेनेवा की एलेन रोकस तथा सिगापुर की क्रिश्चियन नायन ने किया था। कार्यशाला 29.9.93 से 2.4.93 तक चली। इसका आयोजन नई दिल्ली के वार्ड डब्ल्यू.सी.ए. में किया गया था। 31.3.93 को कार्यशाला में भाग लेने वाले सदस्यों को ऐस्कॉर्ट ट्रैक्टर तथा डिबीजन में ले जाया गया जहाँ ऐस्कॉर्ट ट्रैक्टर व फोर्ड ट्रैक्टर जमा किये गये थे। इसके अलावा वे एक टेलिकम्युनिकेशन फैंट्री तथा लघु कपड़ा फैक्ट्री (ओखला) भी गये।

चूँकि कार्यशाला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बारे में थी अतः ज्यादा जोर प्रशिक्षण के तरीकों पर दिया गया।

कार्यशाला के सामने निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये :

1. भारत में लेबर यूनियनों में कार्यरत महिलाओं को व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण प्रशिक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी देना था।

2. महिला उद्यमियों में कार्यस्थल पर पैदा होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

3. व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा पर्यावरण के संबंध में कार्योन्मुख प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

4. श्रम संगठनों के स्वास्थ्य व सुरक्षा प्रतिनिधियों के रूप में भारत में महिलाओं का विकास।

भाग लेने वाले सदस्यों से कहा गया कि यदि वे आवश्यक समझें तो इन उद्देश्यों में और कोई उद्देश्य भी जोड़ें। हमने सुझाव दिया कि जागरूकता बढ़ाने के अलावा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी विचार-विमर्श होना चाहिए जैसे नये प्रावधान लागू करना, वर्तमान प्रावधानों को कार्यान्वित करना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उचित मशीनरी विकसित करना। लेकिन अन्य लोगों ने सोचा कि यह कार्यशाला की सीमाओं से परे है।

भाग लेने वालों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सीटू की हम दोनों सदस्याएं एक ही ग्रुप में थीं। एच.एम.एस. की एक प्रतिनिधि हमारे ग्रुप में थी। एक ग्रुप में केवल एच.एम.एस. के सदस्य थे व दूसरे में इंटक व एच.एम.एस. के प्रतिनिधि थे।

अध्ययन व विचार-विमर्श के लिए 11 मॉड्युलस दिए गये थे। वे थे :

1. व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा लागू करना।
2. काम के समय आपका शारीरिक स्वास्थ्य।
3. खतरों की रोकथाम।
4. काम के समय शोर।

5. प्रावधान व उनका कार्यान्वयन ।
6. कार्यस्थल पर रसायन ।
8. एरगॉनॉमिक्स ।
9. काम के स्थान पर स्वास्थ्य व सुरक्षा समितियों का उपयोग करना ।
10. पुरुष तथा महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा ।

आई.एल.ओ. के प्रतिनिधियों ने पहले शिक्षण पद्धतियों, वयस्क प्रशिक्षण पद्धति तथा सामूहिक विचार-विमर्श के लाभों के बारे में चर्चा की। इसके बाद प्रत्येक समूह से कहा गया कि वह 'कार्यस्थल पर रसायन' तथा 'स्वास्थ्य व महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा' विषय को छोड़कर कोई भी विषय प्रशिक्षण के लिए चुन लें। इन दो विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण दिया। हमारे ग्रुप ने 'खतरों की रोकथाम' विषय चुना व दूसरे ग्रुप ने 'कार्यस्थल पर शोर' तथा 'काम के स्थान व स्वास्थ्य व सुरक्षा समितियों का उपयोग विषय चुना'। समूहों को पहले सिखाई गयी प्रशिक्षण पद्धतियों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमारे ग्रुप ने खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए एक नाटक रखा व उसके बाद खतरों की रोकथाम के बारे में समझाया। का. सञ्चालन के खतरों की रोकथाम के उपाय के रूप में खतरनाक मशीनरी का इस्तेमाल बन्द करने की सलाह दी। इसने प्रशासनिक उपायों की सीमाओं के बारे में समझाया तथा उन्हें उचित नियमों व अनुपालन मशीनरी से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

सिंगापुर की आई.एल.ओ. प्रतिनिधि क्रिस्टीन नाथन ने हमारी बातों से सहमति प्रकट की तथा भारत में निर्माण उद्योग के अपने अनुभवों से इन विचारों को और समृद्ध किया।

अन्त में ग्रुपों के प्रदर्शन का लेखा-जोखा किया गया। पहले स्वयं ग्रुप ने अपने काम-काज की जांच-परख की व बाद में आई.एल.ओ. के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया।

तीसरे दिन कार्यस्थलों का दौरा किया गया तथा उससे अगले दिन वहाँ के स्वास्थ्य संबंधी खतरों व उनकी रोकथाम के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। एच.एम.एस. ने 'एस्कॉर्ट' व 'कपड़ा फैक्ट्री' के बारे का प्रबंध किया जहाँ वह एकमात्र यूनियन है।

कार्यशाला के आखिरी दिन भारत में 'एड्स' पर एक वीडियो फिल्म दिखाई गई तथा उसके बाद पूरी कार्यशाला का लेखा-जोखा किया गया। भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि कार्यशाला लाभ-रही। यह सुझाव दिया गया कि लगभग एक वर्ष बाद इसी प्रकार की एक और कार्यशाला आयोजित की जाये जिसमें सुरक्षा के उपायों तथा प्रशिक्षण पद्धतियों आदि के प्रभाव पर विचार किया जाये तथा अगली कार्यशाला विचार-विमर्श के लिए कुछ चुनिंदा मुद्दे अपनाये जायें जिन पर विस्तार से चर्चा हो।

आई.एल.ओ. के निदेशक ने सभी भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

इस बात पर सहमति हुई कि हम स्वास्थ्य व सुरक्षा के खतरों के बारे में अपनी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करें तथा उनके माध्यम से मजदूरों को प्रशिक्षित करें। यह भी तय हुआ कि स्थानीय उद्योगों की स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाये तथा उनके बारे में तथ्यों का संग्रह व आदान-प्रदान किया जाये।

सीटू की हम दोनों साथियों ने पहली बार ऐसी किसी कार्यशाला में भाग लिया था अतः हमें यह पता नहीं था कि हमें अलग-अलग ग्रुपों में होना चाहिए। हम पास-पास बैठे थे इसलिए एक ही ग्रुप में रहें। हम दोनों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अपने विचार रखे।

व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करती हूँ कि कार्य-शाला लाभदायक रही हालाँकि पाँच दिन का समय बहुत अधिक था शायद यह तीन दिन में भी पूरी हो सकती थी।

शिक्षण की जो पद्धतियाँ सिखलाई गईं जैसे छातों का सहयोग लेना, उनके विचार जानना तथा दृश्य-श्रव्य सहाय्यों का उपयोग करना, वे हमारे लिए स्थानीय स्तर पर मजदूरों को प्रशिक्षित करने में सहायक हो सकती हैं। मैं महसूस करती हूँ कि हमारी यूनियन की गति-विधियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे कार्य-स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य के खतरों तथा उनके लिए अपनाये जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक हों।

थाईलैंड में फैंक्ट्री में लगी आग से 240 महिला उद्यमियों की मृत्यु

पिछले सोमवार को थाईलैंड में लगी आग ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस आग में 240 मजदूरों की मृत्यु हो गयी (इनमें से अधिकतर महिलाएं थीं व कुछ गर्भवती थीं)। स्थानीय मजदूर समूहों का खयाल है हताहतों की संख्या 300 तक होगी क्योंकि अनेक बचती अभी भी लापता हैं। जहां एक ओर सरकार ने घोषणा की है कि जांच चल रही है तथा दो सप्ताह के अन्दर जांच के नतीजे प्रकाशित कर दिये जायेंगे वहीं दूसरी गैर-सरकारी स्थानीय संगठनों को चिन्ता है कि स्वतंत्र जांच के बिना सच्चाई को छिपा दिया जायेगा तथा मजदूरों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के वास्तविक मुद्दे को दबा दिया जायेगा।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में फैंक्ट्री में आग लगने की यह तीसरी घटना है। 1989 में लगी आग के कारण फैंक्ट्री चार माह तक बन्द रही। तथापि, सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की बजाय कार्यस्थल को नोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा जहां ज्वलनशील पदार्थों को जमा कर दिया जाता था तथा काम के समय कार्यस्थल को सामान चोरी होने के डर से बाहर से बन्द कर दिया जाता था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दो संकरी सीढ़ियां थीं जहां दो मजदूर आग लगने के दौरान कुचलकर मर गये। इसके बाद भी फैंक्ट्री में बेताबमी चिन्ता, निकलने के रास्तों व आग से बचने के अन्य उपायों की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

हालांकि मजदूर फैंक्ट्री में आग के खतरों से खतरों से परिचित थे लेकिन वे उससे बचाव के उपायों की मांग नहीं कर सके क्योंकि प्रबंधकों द्वारा सूनियम की गति-विधियों को हतोत्साहित किया जाता था। दरअसल इसी वर्ष मजदूरों को 125 वहत (लगभग 5 अमरीकी डॉलर) का न्यूनतम दैनिक वेतन प्रदान किया गया।

कादर इंडस्ट्रियल (थाइलैंड) का मालिकाना हक संयुक्त रूपसे कादर इंडस्ट्रियल (एच.के.), जिसके पास 40 प्रतिशत शेयर है, चारों पोपकंड ग्रुप (थाइलैंड) तथा ताइबानीज कम्पनी, थाई फू के पास है। इसकी स्थापना 1988 में खिलौने बनाने के लिए की गयी थी। इसमें लगभग 2000 महिलाओं को रोजगार दिया गया

जिनमें से अधिकतर ग्रामीण महिलाएं थीं। फैंक्ट्री में अनेक कैजुअल मजदूर व अस्थायी मजदूरों को भी रखा गया जिनमें कम से कम 120 छात्र थे।

आग के बाद कादर इंडस्ट्रियल (एच.के.) के मालिक समूहों में से एक हांगकांग होस्किंग ने तुरन्त कहा कि "दुर्घटना का समूह पर विशेष आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी के लाभ में समूह का हिस्सा बहुत थोड़ा रहा है।" (द नेशन, बैंकॉक, 13 मई, 1993)। जैसा कि थाई अम संगठन ने कहा कि इस तरह के वक्तव्य से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मान-सिक्ता का पता चलता है जिन्हें इसानों की जिन्दगी से ज्यादा दिलचस्पी पैसे में है। तथापि, कादर इंटरनेशनल की चीन में ऐसी ही डोंगुअन, स्नेहशन व कंटन में ऐसी ही फेक्ट्रियां हैं जिनमें अधिकतर युक्तियां कार्यरत हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार डोंगुअन की फैंक्ट्री में 1990 में एक जबर्दस्त आग लगी थी, पिछले महीने भी एक मामूली आग लगी थी। (मिंग थाओ डेली, हांगकांग, 15 मई, '93)

कादर फैंक्ट्री खिलौने, बैग व अन्य प्लास्टिक के सामान बनाती है जिनका अमरीका को निर्यात दिया जाता है तथा बचा हुआ माल यूरोप को भेजा जाता है। अमरीकी ग्राहकों में ग्युयार्क की कॉमनवैल्थ टॉय एंड नौवली कं. शामिल है। यूरोप में कादर इंडस्ट्रियल (थाइलैंड) अमरीका की टॉयको टॉयज के लिए खिलौने बनाती है।

कादर इंडस्ट्रियल (थाइलैंड) ने दुर्घटना में मारे गये मजदूरों के परिवारों को 6 माह के वेतन के समान राशि, लगभग 20 हजार वहत (लगभग 800 अमरीकी डॉलर) का भुगतान करने तथा घायलों को दो माह का वेतन प्रदान करने का वादा किया है। थाई सरकार ने 10 हजार अमरीकी डॉलर से 15 हजार अमरीकी डॉलर के भुगतान का वादा किया लेकिन ये भुगतान सभी होगा जब मृतकों के संबंधी मृत्यु की पुष्टि करे तथा उचित कागज जमा किये जायें। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि स्थानीय प्रबंधक के छः प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा।

इस बीच सरकार ने उस इलाके की सेना व पुलिस द्वारा नाकेबन्दी करा दी है। गैर सरकारी संगठनों व श्रम संगठनों के उस इलाके में पहुंचने पर रोक है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वतंत्र जांच संभव नहीं है। आग लगने के बाद अधिकतर मजदूर दुधर-उधर बिखर गये हैं। उनमें से अनेक अब दूसरी कनिष्ठियों में काम कर रहे हैं। स्थानीय संगठनों का विचार है कि यह सरकार की मजदूरों को संगठित होने से रोकने के लिए पुनर्वासित करने की सोची-समझी योजना है। दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए अनुदान जमा करने जैसी गतिविधियों पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा इस प्रकार जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटाया जा रहा है।

जिमल रणदिवे द्वारा काबर इंडस्ट्रियल (हार्गकांग), हार्गकांग को निम्नलिखित तार भेजा गया व उसकी प्रति कमेटी फॉर एशियन वोमेन (सी.ए.डब्ल्यू.) हार्गकांग को भेजी गयी :

हम सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने के लिए कंपनी की भर्त्सना करते हैं जिसके कंपनी के 300 मजदूर की मौत हुई। इसका पूरा मुआवजा दिया जाये।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध

[अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों ने अपनी मुख्य मांगों से संबंधित एक जापन प्रधानमंत्री को दिया। उनकी मांगों के समर्थन में संसद सदस्य कामरेड समर मुखर्जी द्वारा प्रधानमंत्री के नाम लिखा हुआ पत्र इस प्रकार है—संपादक]

चार प्रमुख केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की नर्सों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान दिलाने के लिए 28.5.93 को संयुक्त पत्र लिखा। इसका अक्षर 13.5.93 को ए.आई.एम.एस. नर्सों के संघ द्वारा आपको दिये जापन में भी दिखा गया

इस प्रख्यात संस्थान की नर्सों पर संस्थान के प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे आचरण पर इन संघों के नेताओं ने अचरज व्यक्त किया। यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि नर्सों के सेवा भाव के कारण ही इस समय यह संस्थान न केवल देश में अपितु एशिया में बुलाईयों को छू रहा है।

मुझे यह देखकर बहुत अचम्भा हुआ है कि ए. आई. एम. एस. के नर्सिंग स्टाफ को यह न्यूनतम सुविधाएं तथा नौकरी की सुविधाएं भी नहीं दी गई जो कि देश के अन्य सशरी सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। मैं यह नहीं समझ पाता कि इस संस्थान की नर्सों तथा अन्य सरकारी अस्पतालों की नर्सों के बीच भेदभाव बनाए रखने के पीछे क्या तर्क है।

इस मामले का दूसरा अत्यंत आवश्यक बिन्दु वास्तव में बड़ी उलझन पैदा कर रहा है क्योंकि विशेषता के नाम पर नर्सिंग स्टाफ के विकेन्द्रीकरण सहित ए. आई. आई. एम. एस. की कई ईकाइयों का विकेन्द्रीकरण सहित प्रस्ताव

पर प्रयास चल रहे हैं। संस्थान के नर्सिंग स्टाफ को दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तावित प्रयास न केवल हमारे लिए मरीजों के लिए भी हानिकारक होंगे। केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने बहुत बढ़िया एवं उपयुक्त ढंग से कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार इस संस्थान के मानव संसाधन प्रबन्धन की खराब स्थिति का उल्लेख किया है। मैं ए. आई. आई. एम. एस. नर्सिंग स्टाफ की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूँ तथा नर्सिंग स्टाफ की विवकतों को कम करने के लिए आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करता हूँ। नर्सिंग स्टाफ की जायज मांगों का शीघ्र निबटारा करना इस व्यापित प्राप्त संस्थान के अपने हित में होगा।

त्रिपुरा के साथियों को हार्दिक बधाई

माकपा की अभिभूत कर देने वाली विजय के लिए त्रिपुरा के सभी साथियों व जनता को हार्दिक बधाई।

जिमल रणदिवे
9-4-1993

प्रिय कॉमरेड जिमल दी,

विधान सभा चुनावों में हमारी ऐतिहासिक विजय के लिए भेजे गये बधाई तार पर अपना धन्यवाद प्रकट करने में हुई देरी के लिए हमें खेद है। हमारे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी की। मणिक सरकार से प्राप्त हो जायेगी।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय
ह०/-
(नूपेन चक्रवर्ती)
13-4-1996

के प्रति खल में, मांगों की प्रकृति तथा उच्चा कांक्षा में भी परिवर्तन आया है।

सजिनी

खजा खण्ड के दो निकटवर्ती गांव लुकुई-केनाली तथा कुरकुटिया अन्य पारम्परिक आतीय गांवों की तरह ही लगते हैं वहाँ की सजी-घजी झोपड़ियाँ, भूसी कालने के पैडल और सुब्रों के झुंड। परन्तु शाम के समय विजली के बल्ब गांव की जगमगाती हुई जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। यह गांव लोकदीप (लोगों के लिए प्रकाश) कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत कृत किया गया है। लुकुई केनाली में मोटर मकैनिक, छोटे दुकानदार, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के साथ छोटे एवं बड़े किसान भी हैं परन्तु भूमिहीन मजदूर लोग नहीं हैं। पंचायत, सी.पी.आई. (एम) तथा प्रशासन द्वारा चलाए गये आन्दोलन के बाद इस गांव में किसी भी आयु का कोई भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है।

इसमें हैरानी की बात नहीं कि सजिनी तो आठवीं कक्षा तक पढ़ी घरेलू पत्नी हैं। वह इस क्षेत्र से सी.पी.आई. (एम) साक्षरता प्रचार के खण्ड स्तरीय समिति की नियुक्त सबसे शिक्षात स्वयंसेवक अध्यापिका हैं। जब हम सजिनी से मिले तो वह कुएँ से पानी खींच रही थी। जब हमने उस शर्मिली, दुबली पतली सजिनी से पूछा कि 'किस चीज ने तुम्हें चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित किया' तो उसने तीक्ष्ण जवाब दिया। "यह मेरे अकेले की प्रेरणा नहीं है। तुम जानते हो, सारा गांव ही प्रेरित है। हमने अपने लिए जीवन बदल लिया है। परन्तु अभी यहाँ बहुत कुछ करना है। यहाँ की हर औरत को खड़े होने के लिए बुलावा आया है और हम भी उसके अनुरूप तैयार हैं।" सजिनी मानती है कि वह प्रशासन की जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं है परन्तु उसे विश्वास है कि आने वाले समय में पार्टी तथा पंचायत के भूतपूर्व सदस्य उसे सब कुछ बता देंगे।

छाबीरानी

बांकुरा-मिवनापुर बाडर पर पड़ने वाले छोटे से गांव लिपिडंगा से सी. पी. आई. (एम) की ब्लाक स्तरीय प्रत्याशी छाबीरानी हंसवा के लिए यह संघर्ष बहुत कठिन है। उसे शारखंड पाटियों के अपने ही समुदाय के सिद्धांत हीन कन्वर्सेटिव और प्रतिक्रियावादी प्रतिनिधियों का

सामना करना पड़ रहा है। शारखंड पार्टी के नेता अब अपने पीछे से मिलने वाले सहयोग में भारी कमी का अनुभव कर रहे हैं, अब उन्होंने जन-जातिय प्रधान तीन जिलों के क्षेत्रों के बहुत बड़े हिस्से में आतंक पूर्ण गति-विधियों को अपना लिया है। हाल ही में शारखंडियों द्वारा सी.पी.आई. (एम) के छः कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उनकी लाश लिपिडंगा के पास पायी गई जिससे क्षेत्र में राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया। शारखंड नेता अपनी कुंठा से बाहर निकल कर अलग राज्य के लिए अन्तिम लड़ाई फाइनल फाइट की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी ओर सी.पी.आई. (एम) इस बिनाश-कारो वर्ष के विरुद्ध लड़ने के लिए जन-जातिय तथा गैर जन जातीय एकता की आवश्यकता पर बल दे रही है।

28 वर्षीय छाबी रानी दो बच्चों की माँ होने के साथ अपने पति घरन की अच्छी जीवन साथी है। वह क्षेत्रों में अथक कार्य करने के साथ गांव के राजनीतिक मुद्दों की भी हल करती है। छाबी रानी ने यह पार्टी साक्षरता प्रचार के दौरान अपनायी थी वह अपने प्रत्यक्ष जान बोध में उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट है। बादलों से भरे तीसरे पहर के समय अपने बालों की चोटी बनाते हुए वह सन्ध्याली लहजे में बोली :

"अलग राज्य के नारे से आदिवासी अब उलझन में नहीं हैं। प्रश्न भूमिका है, आत्म सम्मान का है। पंचायत ने निहित जगहों को गरीब जन-जातियों में बाँट दिया है। सान्ध्यायालों के बारे में अपमानजनक बातें करने का अब किसी में साहस नहीं जैसे कि वे पहले करते आए हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं बड़े-बड़े राजि केन्द्रों में पढ़ते हैं। इसके बतिरिक्त कम्प्युनिस्टों ने देश की समस्याओं से भी परिचित कराया है। अब हम बहुत अधिक सजग हो गये हैं" छाबीरानी मानती है "शुरू में अपने आपको कमजोर समझती थी। परन्तु अब सब ठीक है। जन-जातीय महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं कि उनमें से संकड़ों महिलाएं चुनावों में खड़ी हुई हैं।" वह अपने पति की ओर इशारा करते हंसते हुए बोली, "हमें उनसे बेहतर करके दिखाना है।"

मकलु, सजिनी तथा छाबीरानी उन 70 हजार महिला प्रत्याशियों में से हैं जिन्होंने इस वर्ष चुनाव लड़ा। उनके लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के परिणामस्वरूप कुल

[शेष पृष्ठ 24 पर]

शबाना आजमी कहती हैं...

मैंने हमेशा यह माना है कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग-अलग फूल अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुरक्षित रखकर उसे एक रंगीन स्वरूप देते हैं। इसके विपरीत इसको एक तपती कड़ाई में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें व्यक्तिगत पहचान लिंग, राष्ट्रियता, क्षेत्र, धर्म, व्यवसाय आदि से है। पहचान को इनमें से सिर्फ किसी एक बात से कैसे परिभाषित किया जा सकता है ?

पहचान की इस जटिलता में पड़े बिना धर्मनिरपेक्ष रहना जा सकता है, चाहे हम हिन्दू हों चाहे मुस्लिम। एक सांप्रदायिक व्यक्ति की बेचनी उसे अपने आपको धर्म के आधार पर व्यासंगत ठहराने के लिए मजबूर करती है। कोई धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता।

सांप्रदायिकता को हिन्दू, मुस्लिम या सिख के खांचों में नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचार के रूप में समझना

होगा। इतिहास को सांप्रदायिक स्वर्यों के लिए तोड़ा-मरोड़ा जाता है।

संघ परिवार जिस हिन्दुत्व का प्रचार करता है वह हिन्दुत्व नहीं है। हिन्दुत्व के सही अनुयायी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी व डॉ. रामकृष्णन थे। संघ परिवार फासीवाद का प्रचार कर रहा है। हर हिन्दू को इस बात का फैसला करना है कि उसे गांधी व विवेकानन्द के हिन्दुत्व को अपनाना है या साध्वी अच्युतभारा व अशोक सिंघल के हिन्दुत्व को।

लोकतांत्रिक ताकतों का एकमात्र हथियार सत्य हो सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हिन्दुओं में कुछ असंतोष था जिसका संघ परिवार ने दोहन किया। मुस्लिमों की अंतरआत्मा को टटोलने की आवश्यकता है कि कुछ शिकायतों का जायज आधार है।

प० बंगाल : 1993 के पंचायत चुनाव

तालिका-1

पिछले चार पंचायत चुनावों में सीटों, मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या

	1978	1983	1988	1993
कुल स्थान				
जिला परिषद	648	678	658	656
पंचायत समिति	8467	8664	9128	9455
ग्राम पंचायत	46,485	46,153	52,520	61,012
कुल मतदाता	2,50,00,000	2,20,07,994	2,63,55,044	3,03,64,513
कुल मतदान केंद्र		18,984	31,771	37,586

तालिका-2

पिछले चार चुनावों में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों की कुल संख्या

	1978	1983	1988	1993
ग्राम पंचायतें	3242	3305	3227	3222
पंचायत समितियाँ	324	339	329	328
जिला परिषदें	15	15	15	16

बिहार सरकार के पत्रांक 1373, आंगनवाड़ी महिलाओं पर जुलम

आप सभी अवगत हैं कि पिछले दो दशकों से हम सभी आन्दोलनरत रहकर अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, किन्तु बिहार सरकार के भ्रष्ट अफसरशाही के चलते आज तक हमारी मांगें उपेक्षित रही हैं। संघ के निर्णयानुसार आप सबों ने अपने-अपने परियोजना से लेकर जिला स्तर पर घरना कार्यक्रम चलाकर 1993 के वर्ष को 'संघर्ष वर्ष' का सही रूप प्रदर्शित किया है, जिसके चलते आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

यह बात सर्वविदित है कि जब-जब श्रमिक संघर्ष पर उत्तारू होते हैं तो सरकारी दमनचक्र भी उसी अनुपात में चलना आरम्भ कर देता है। आपके संगठन के साथ भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। बिहार सरकार के पत्रांक 1373 दिनांक 11.6.1992 ने हम सबों के ऊपर भयंकर वज्रपात किया है। आश्चर्य एवं शोक का विषय तो यह है कि एक ओर तो बिहार के मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय की बात करते हैं और दूसरी ओर बिहार में कार्यरत सभी समेकित बाल विकास परियोजना में उक्त पत्र के निर्देशानुसार भयंकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य की अनेक परियोजनाओं में उक्त काले निर्देश के तहत हजारों सेविकाओं की छंटनी कर दी गयी है जो अपने आप में सरकार के मुँह पर एक कलंक है क्योंकि इससे ज्यादा महिला उत्पीड़न और न्या हो सकता है कि वर्षों से कार्यरत महिलाओं की सेवा समाप्त की जा चुकी है और यह भ्रष्ट सरकार चुप्पी साधे हुए है।

सोना जब-जब आग पर तपाया जाता है तो उसमें और विचार उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह हम सबों में भी सरकार की दमनात्मक कार्रवाई से नया जोश-खोरोश पैदा हुआ है और कई गुणा अधिक लगन के साथ आन्दोलन पर उतर आये हैं। आन्दोलनात्मक कार्यक्रम की सूचना पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 1292/92 दिनांक 17 दि. 1992 के द्वारा आप सभी को दी जा चुकी है उस पत्र की पत्र प्रतिलिपि पुनः संलग्न करते हुए आप सभी से अनुरोध है कि वि. 29 जून '93 तथा 30 जून '93 को

अम्बेडकर चौक, बेली रोड, पटना में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर घरना कार्यक्रम को सफल करें। आप लाये जिससे कि संघर्ष का न्याय भार वहन किया जा सके। ध्यान रहे कि संघर्ष लम्बा हो सकता है।

दिनांक 28 जून 93 को राज्य शाखा की बैठक दिन में 12 बजे लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में बुलायी जा रही है जिसमें घरना कार्यक्रम तथा अगली रणनीति पर विचार किया जायेगा, उक्त बैठक में भी आपकी उपस्थिति प्राप्ति है।

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका एवं कर्मचारी संघ की मुख्य मांगें :

1. सेविका-सहायिका को सेवा का 88 के हड़ताली कर्मचारियों से समक्षीते के समय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आलेख में अविलम्ब सरकारीकरण किया जाय।

2. महिला पर्यवेक्षिका के पद पर सीधी बहाली को बंद किया जाय और उक्त पद को सेविका की प्रोन्नति से भरा जाय।

3. आंगनवाड़ी सेविका एवं कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार की जाय तथा उनकी सेवा सम्पुष्ट की जाय।

4. बाल-विकास परियोजना पदाधिकारी के सत्-प्रतिष्ठत पदों को महिला पर्यवेक्षिका की प्रोन्नति भरी जाय एवं अन्य विभागों से आए पदाधिकारियों को उनके पैतृक विभागों में लौटाया जाय।

5. आंगनवाड़ी सेविका/सहायिकाओं का वेतनमान निर्धारण किया जाय। तत्कालिक तौर पर मानदेय क्रमशः 600 एवं 400 रुपये प्रतिमाह किया जाय।

6. केन्द्र पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की जाय।

7. केन्द्र तक पोषाहार को सरकारी व्यवस्था से

पहुँचाया जाय तथा जलावन की व्यवस्था नियमित रूप से की जाय।

8. बरी मटर जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है बन्द करके पहले की तरह हरी सब्जी खरीदने का पुन. आदेश दिया जाय।

9. विभागीय बैठक में भाग लेनेवाली सेविका को यात्रा भत्ता दिया जाय।

10. बाल विकास से सम्बन्धित राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय बैठक में आंगनवाड़ी सेविका के एक प्रतिनिधि को निम्नित तौर पर शामिल किया जाय।

11. खाद्यान की मात्रा बढ़ाई जाय।

12. आंगनवाणी सेविका एवं सहायिकाओं का आर्थिक शोषण बन्द किया जाय।

13. महिला पर्यवेक्षिकाओं को केन्द्र भ्रमण के समय एक सहायिका दी जाय।

14. बर्दी या बर्दी भत्ता दिया जाय।

15. समय पर मानदेय का भुगतान किया जाय।

16. अभिश्चम की राशि में वृद्धि की जाय।

17. मकान भाड़े की दर में वृद्धि की जाय।

18. सेविका एवं सहायिकाओं की छंटनी बन्द की जाय।

अन्त में वामपंथी दलों के सभी मानय सांसद तथा माननीय विधायकों से मासिक अपील है कि वे धरनास्थल पर पधार कर घनाधियों को सम्बोधित करने का अनुग्रह करना चाहें। सभी श्रमिक संगठनों से यह अनुरोध है कि वे हम महिलाओं के इस आन्दोलन को सहयोग देने की कृपा करे, जातव्य है कि बिहार राज्य खेत-खलिहान महिला मजदूर संघ की महामंत्री श्रीमती अंजू पाण्डेय 'दत्तमयी' से इस आन्दोलन को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अन्त में मैं अपने सभी साथियों से अपील कर रही हूँ कि वे हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर अपनी फौलादी ताकत का परिचय दें।

महिला उत्पीड़न : अमरीका भी पीछे नहीं

महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति केवल तीसरी दुनिया तक सीमित नहीं है। इस मामले में बंगाल के उन्नत समझे जाने वाले देशों की स्थिति भी उतनी ही खराब है। यह तब है जबकि तीसरी दुनिया के देशों की महिलाओं को शिखा और स्वतंत्रता के मामले में काफी पिछड़ा माना जाता है। अमरीका में सीनेट की न्यायिक मामलों की समिति ने हाल में इसी रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका में बलात्कार के लगभग आधे (48 फीसद) मामले बिना सुनवाई के खत्म कर दिये जाते हैं। इसी तरह बलात्कार के मामलों में एक तो सजा ही बहुत कम लोगों को होती है और जिन्हें होती भी है वे साल भर के अन्दर-अन्दर बापस घर लौट आते हैं। समिति ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बताया कि बलात्कार के इन आरोपियों में केवल एक को सजा हो

पाती है।

बासिगटन पोस्ट में इस रिपोर्ट का विवरण छपा है। विवरण के अनुसार कसूरवार को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है लेकिन ऐसा होता नहीं, न्यायाधीश आमतौर पर उन्हें बर्खा देते हैं। कह दिया जाता है कि अपराधी ने ऐसा अपराध पहली दफा किया है यानी सजा के लिए कम से कम दो बार अपराध किया जाना चाहिए।

अमरीकी पुलिस का रवैया भी वही है जो और देशों की पुलिस का रहता है। पहले तो पुलिस मामले दर्ज करती ही नहीं। ऐसे मामले तो बिल्कुल दर्ज नहीं करती जिनमें अपराधी और अपराध के मुक्त भोगी पूर्वपरिचित हो। जबकि ज्यादातर बलात्कार ऐसे ही मामलों में होते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्पीड़न के 84 फीसद मामले तो दर्ज ही नहीं होते।

इंटक के गुन्डों द्वारा सीटू मजदूरों की हत्या की सीटू व प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन द्वारा भर्त्सना

सीटू व प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन ने निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया।

सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन इंटक के गुंडों द्वारा 17 सीटू मजदूरों की अघन्य हत्या की कड़ी भर्त्सना करती है जिन्होंने अपने हमले के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले के बतारहट चाय बागान क्षेत्र में अन्य अनेक सीटू मजदूरों को भी जस्मी किया। यह हमला बिना किसी भड़कावे के तथा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अंधेरे में सीटू की बैठक पर हमला करते समय हमलावर बचने के रास्तों को बन्द करना नहीं भूले। बैठक पर हमला करने के अलावा उन्होंने आस-पास के अनेक गांवों में भी लूटपाट की। यह हमला आग्नेयास्त्रों, बमों व अन्य खतरनाक हथियारों से किया गया तथा पुलिस की कार्रवाई को मुश्किल बनाने का भी प्रबंध किया गया था।

अदूरदर्शी इंटक नेताओं ने यह नहीं सोचा कि उनके उस हमले से स्वस्थ मजदूर आन्दोलन के लिए माहौल खराब होगा तथा इससे जो स्थिति पैदा होगी वह मजदूर-हितों के सख्त खिलाफ होगी। सीटू को आशा है कि इंटक का उच्चस्तरीय नेतृत्व इस ओर ध्यान देगा तथा न केवल इस मामले की जांच करेगा बल्कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को भी रोकेगा।

मजदूरों ने स्थानीय व जिला स्तर बन्द के माध्यम से अपना प्रतिरोध उचित रूप से प्रकट किया है। सीटू तथा प्लांटेशन मजदूर फेडरेशन मजदूरों से अपील करती है कि वे इस अघन्य कांड पर अपना विरोध प्रकट करें।

सीटू तथा प्लांटेशन मजदूर फेडरेशन मांग करती है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाये तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाये।

सीटू तथा प्लांटेशन मजदूर फेडरेशन घायलों के प्रति हाबिक सहानुभूति तथा मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

काँ. क्रिस हानी की हत्या

10 अप्रैल, 1993, शनिवार को लगभग 10.00 बजे काँ. माटिन येम्बयाली (क्रिस) हानी, दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य तथा उम्मान्तो वी सियवे के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टॉफ की डॉन पार्क में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी।

काँ. क्रिस हानी की हत्या ऐसे समय में हुई जब बहु-दलीय विचार-विमर्श आरम्भ होने के कारण जनता में शान्ति व सद्भाव की उम्मीद बचने लगी थी। पिछले सप्ताह शान्ति के राष्ट्रव्यापी प्रचार में काँ. क्रिस हानी स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। हाल ही में गुरुवार, 8 अप्रैल को उन्होंने 'शान्ति' के विषय पर एस.बी.सी. के एक कार्यक्रम में भाग लिया था।

मुक्ति संघर्ष के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता तथा रंग-भेद के पुरजोर विरोध के कारण काँ. क्रिस हानी एक अरसे से रंगभेदी शासन के एजेंटों के हत्या प्रयत्नों का निशाना रहे थे। इन प्रयासों में एक तथा आग्राम जा गया जब पिछले सप्ताह एक बैंक डकैती का अपराधी, जिस पर मुकद्दमा चलाया जा रहा था उसी नाम पुलिस हिरासत से भाग गया।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को विश्वास है कि उनकी हत्या के पीछे बड़ी लोग पाये जायेंगे जो अरसे से उनकी समाप्ति चाह रहे थे। हम अपने सभी समर्थकों से अपील करते हैं कि वे शान्त रहे हैं तथा शान्ति प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करने के इरादे से की जाने वाली भड़काने की कार-बाइयों में न आएँ।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस काँ. क्रिस हानी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपना जीवन दक्षिण अफ्रीका में शान्ति व लोकतंत्र के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने साहस व निष्ठा के साथ ए.एन.सी. तथा एस.ए.सी.पी. की सेवा की। काँ. क्रिस हानी अपनी पत्नी डिम्को व तीन बच्चियों के रूप में जीवित हैं।

कर्नाटक राज्य बीड़ी मजदूर फेडरेशन का छठा सम्मेलन

सम्मेलन का आयोजन 28 व 29 तारीक को मैंगलूर में किया गया। सम्मेलन में काँ. बिमल रणदिवे तथा काँ. सी. कानन को आमन्त्रित किया गया था तथा वे आयीं। सम्मेलन की अध्यक्षता काँ. सुर्म नारायण राव ने की। कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला मैंगलूर गणेश बीड़ी व अन्य मार्कों के लिए प्रसिद्ध है। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीड़ी बनाने वालों की कुल संख्या पांच लाख तक है। जबकि राज्य सरकार का दावा है कि कुल 3.5 लाख बीड़ी मजदूर हैं। मालिकों व ठेकेदारों द्वारा शोषण, कम वेतन तथा रोजगार सुरक्षा के अभाव में इन मजदूरों की जीवन स्थितियाँ प्रोचनीय हो गयीं हैं, हालांकि उनके कल्याण के लिए प्रति हजार बीड़ियों पर 100 रु. एकड़ किये जा रहे हैं। लेकिन कल्याण योजनाएं ठीक से नहीं चलाई जा रही हैं क्योंकि मजदूरों को परिचय-पत्र नहीं दिये गये हैं। हालांकि अनेक इलाकों में महिलाएं कार्यरत हैं लेकिन उन्हें गर्भावस्था मुद्दियों नहीं दी जा रही क्योंकि मालिकों ने महिलाओं के बजाय पुरुषों के नाम का पंजीकरण किया है। चूँकि उन्हें सामान खरीदने के लिए कम धन दिया जाता है अतः अच्छा माल खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। सम्मेलन में इन सब समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ।

28 अप्रैल को 11 बजे साउथ कन्नड़ टाइल् वर्क्स यूनियन हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए काँ. बिमल रणदिवे ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो बीड़ी उद्योग में बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने महिलाओं के विशेष मामलों के बारे में बताया उन्होंने बताया कि पुरुषों व महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली बीड़ियों में कोई अन्तर नहीं है हालांकि महिलाओं को समान वेतन देने से इनकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदारीकरण की नीति अनेक मजदूरों को असंगठित क्षेत्र की ओर धकेल रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चाहती थी कि महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित रहें उन्होंने प्रतिनिधियों से अपील कि कि वे 9 सितम्बर के

भारत बन्द को सफल बनाने के लिए काम करें।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए काँ. सी. कानन ने समान वेतन के लिए संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने बताया कि केरल में बीड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 35.80 रु. प्रति हजार बीड़ी है। यदि वे छः दिन काम करते हैं तथा प्रतिदिन 80 बीड़ियाँ बनाते हैं तो उन्हें एक दिन का अतिरिक्त वेतन मिलता है। उस प्रकार उनका वेतन प्रति हजार बीड़ी 40 रु. होता है। कर्नाटक में न्यूनतम वेतन 26.31 रु. प्रति हजार बीड़ी है। अतः कर्नाटक के मजदूरों के लिए कम से कम 40 रु. प्रति हजार बीड़ी का वेतन पाना संभव है। उन्होंने देश भर में प्रति हजार बीड़ी 5.32 रु. की समान कर दर लागू करने की नीति की ओर इशारा किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि मजदूरों को परिचय-पत्र प्रदान नहीं किये जा रहे हैं तथा इस प्रकार कल्याण आयोग को अपनी जम्मेदारियों से बचने का मौका मिल जाता है। मालावार तथा दक्षिण कांडरा में बीड़ी मजदूरों को संगठित करने के अपने पिछले अनुभव की याद करते हुए उन्होंने उसी जुझारु भावना को पुनः पैदा करने तथा संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बीड़ी मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति के तेलचरी (केरल) में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के फैसले के बारे में बताया।

फेडरेशन के निवर्तमान महासचिव का. मो. दस्तगीर ने सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट रखी। का. नित्यानंद ने रिपोर्ट को पढ़ा जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र था। इसमें न्यूनतम वेतन के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया गया था। विचार-विमर्श में महिलाओं सहित अनेक सदस्यों ने भाग लिया। का. दस्तगीर ने बहस का जवाब दिया।

कर्नाटक स्टेट सीटू के महासचिव का. बी.जे.के. नायर ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जिसकी परिणति 14 जुलाई को अखिल भारतीय हड़ताल में होगी। उन्होंने आवश्यकता-

[शेष पृष्ठ 11 पर]

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. तमिलनाडु का चौथा राज्य सम्मेलन उमा माहेश्वरी

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का चौथा राज्य सम्मेलन 20 अप्रैल, 1993 को ऐतिहासिक शहर सालेम में हुआ।

21 जिलों से 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन एक अध्यक्षमंडल ने किया जिसमें का. देवी परमेश्वरी शामिल थीं। अपने उद्घाटन भाषण में अखिल भारतीय सचिव का. विमल रणदिवे ने बताया कि प्रकार 1979 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक समिति ने महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि एल.आई.सी., जी.आई.सी., बैंक, केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में महिला समितियों की स्थापना में भी डब्ल्यू.डब्ल्यू.सी.सी. महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले पांच वर्षों में समिति का काम सराहनीय रहा है फिर भी बीड़ी, निर्माण, कपड़ा व रबर आदि असंगठित क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सहायक संयोजक ने विचार-विमर्श के लिए रिपोर्ट रखी। लगभग 29 प्रतिनिधियों में विचार-विमर्श मूलतः कार्यस्थलों पर मजदूरों के सामने आने वाली समस्याओं पर केन्द्रित था।

'आईडवा', तमिलनाडु के महासचिव का. पप्पा उमानाथ तथा तमिलनाडु सीटू के महासचिव का. उमानाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। का. उमानाथ ने नागरकोइल सम्मेलन के बाद महिलाओं में पैदा हुई संघर्ष भावना का जिक्र किया। उन्होंने रात की शिफ्ट तथा 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रति प्रबंधकों के रवैये की आलोचना की।

सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये जिनमें, सांप्रदायिकता, आर्थिक नीतियों, बाल-श्रम की समस्याओं तथा कामगार महिलाओं के अधिकारों पर प्रस्ताव शामिल थे।

महिलाओं के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए उनके साथ चलना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए मई-

जून में कामगार महिलाओं का एक और सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया। इसी के तारतम्य में 13 जुलाई को प्रत्येक जिले में घरना कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सम्मेलन के अंत में एक 17 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया गया जिसमें का. उमा महेश्वरी, संयोजक (मद्रास), सहायक संयोजक, का. इन्दिरा, (कन्याकुमारी), ईश्वरी (कोयम्बटूर), का. देवी परमेश्वरी (मद्रास) शामिल हैं।

[पृष्ठ 10 का दोष]

नुसार न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष छेड़ने की अपील की।

सम्मेलन में 40 रु. प्रति 1000 बीड़ी न्यूनतम वेतन तथा कर्नाटक राज्य सूचकांक के अनुसार 5 पैसे प्रति बिन्दु बी.डी.ए. प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई कि यदि कोई मजदूर काम पर आता है और उसे काम नहीं दिया जाता तो उसे 25 रु. भुगतान किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ठेका प्रणाली समाप्त करने तथा नवंबर में कैनोर में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के फैसले का स्वागत किया।

का. विमल रणदिवे महिलाओं की भूमिका तथा उनके सक्रिय होकर आगे आने की आवश्यकता पर पुनः बोलीं। इसके बाद सम्मेलन में कैंडिडेशन कमेटी की रिपोर्ट पास की गयी।

सम्मेलन में निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव किया गया :

बी.जे.के.नायर—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष—मो. इस्तगीर, पद्मावती, के. मूसला महासचिव, के. शेखर, सचिव—नित्यानंद स्वामी, बालकृष्ण शेड्डी व एम. मुल्ला तथा त्रिशूरर सुकुमार। सम्मेलन में 18 सदस्यीय राज्य समिति का भी चुनाव किया गया।

पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा सरकार की पंचायत चुनावों में विशाल सफलता पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं

सी.पी.एम. तथा वाम मोर्चा ने पंचायत चुनाव की कुल सीटों में से लगभग दो तिहाई सीटें जीत कर विशाल सफलता दर्ज की है। ताज़ा रिपोर्ट अनुसार सी.पी.एम. सभी त्रिस्तरीय सीटों पर 36,089 से विजयी हुई जबकि वाम मोर्चा ने कुल 39,442 से। कांग्रेस तथा भाजपा ने सी.पी.एम. के विरुद्ध एक दूसरे से हाथ मिलाकर कुमशः 14,403 तथा 2215 सीटें प्राप्त किए।

परिणामों ने कई लोगों को आश्चर्य चकित किया। परन्तु सी.पी.एम. कैंडिडेटों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले नेताओं को पूर्णतः विश्वास था कि परिणाम वाम पंथी दलों के पक्ष में ही जाएंगे क्योंकि यह पंचायत व्यवस्था में सच्चे तौर पर गरीब ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व देती रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों ने भी दिखाया कि लोगों की भूमि सुधारों का परिचय, अतिरिक्त भूमि के वितरण तथा कई कल्याणकारी लाभ देने पर ही वाम मोर्चा को इन चुनावों में एक बार फिर चुनाव मिला।

इस बार कांग्रेस (आई) तथा भाजपा ने सी.पी.एम. को हराने के इरादे से एक दूसरे की सहायता करने का निश्चय किया और भाजपा ने निर्वाचित होने के लिए वेशम होकर हाबरा प्रशासन से निकाले हुए कांग्रेसी प्रत्याशियों से हाथ मिलाया। कांग्रेस ने अपने 6 दिसम्बर से चले आ रहे धर्म निरेपेक्षता के वायदों को अपने भाषणों में कई बार दोहराया।

परन्तु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पंचायत चुनावों में महिलाओं के 1/3 भाग की विजय। पिछले चुनाव में भी वे पहले से मौजूद थे परन्तु इतने विशाल रूप में नहीं। वास्तविकता यह है कि नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों में महिलाएँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य 60 प्रतिशत हैं, इनमें अकेले एक तिहाई महिलाओं की सीटें निश्चय ही ग्रामीण व्यवस्था में सही ढंग से परिवर्तन लाएंगी।

हाल ही में देवाशीष चक्रवर्ती द्वारा पीपल्स डेमोक्रेसी में "टाइपस ऑफ़ केन्डीडेट्स सी.पी.एम. फिल्डेट" नामक शीर्षक से प्रकाशित विवरण में कुछ निर्वाचित महिला

प्रत्याशियों की जीवन्त तस्वीर पेश की गई है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रति उनके कार्य करने के विश्वास को भी दिखाया गया है।

एक सबल महिला-मकलु मुरमु

बंकुरा जिले की कुशबाना पंचायत तथा लोगों ने अपनी घाटी को हरा-भरा बना दिया उनकी शाम में ढोल की आवाज नई आशा के साथ गूँज रही है। आने वाली पंचायत में कुशबाना का प्रतिनिधित्व 22 वर्षीय सबल महिला मकलु मुरमु द्वारा होना है। खेत में काम करने वाली मकलु कृषि उत्पादन की प्रत्येक जानकारी में प्राकृतिक विशेषज्ञ है। वह एक सी.पी.आई. (एम) प्रत्याशी थी और उसे अपने गाँव के प्रत्येक वोट मिलने का पूरा विश्वास था। मकलु के पति मंसाराम तथा ग्रामीण साधियों को पार्टी से जुड़े रहने में मकलु के समान गर्व महसूस होता है। जिसे वह 'हमारी पार्टी' गरीब लोगों की पार्टी कहती है। वह अपने गाँव के विकास कार्यक्रम के अनुपक्षण की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और यदि आवश्यक हुआ तो पड़ोस के गाँव को भी देख सकती है।

यहाँ बंकुरा जन-जाति जीवन में सुस्पष्ट परिवर्तन हुआ है यहाँ वाम मोर्चा शासन के दौरान 27,000 भूमिहीन जन जातियों को भूमि दी गई। उनमें से 12000 से अधिक ने अपना नाम फसल में बटाईदार वालों में दर्ज करा लिया है जो अपने उत्पादन का वैध हिस्सा प्राप्त करते हैं। लोगों की शुरूआत स्वयंसेवकों के प्रयास और विलेयतः देशज, प्राथमिक ग्रामीण तकनीक से यहाँ की सिंचाई सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। न्यून संसाधनों को काम में लाने, लोगों की शक्ति को दूर प्रकृति के विरुद्ध लड़ने हेतु तथा अविकसित स्थानों के लिए लोगों को तैयार करने में पंचायत ने अक्षीय भूमिका अदा की है। इसके परिणामस्वरूप जन जातीय क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जन जातियों की आर्थिक गतिविधियों पर किए गये विविध प्रयासों ने प्रारम्भ में ही परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। जीवन

कर्नाटक कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक

एम. राजम्मा

कर्नाटक कामगार महिला समन्वय समिति की राज्य समिति की एक स्थापक बैठक 27-4-93 को मैंगलूर में हुई। बैठक का. विमल रणदिवे की अध्यक्षता में 11 वजे आरंभ हुई। मैंगलूर, बंगलूर, हरिद्वर, हुबली, धारवाड़ व कुर्ग जिलों के प्रतिनिधियों ने बहुसंख्य में भागदेवारी की। अधिकतर प्रतिनिधि बीड़ी व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से थे।

मैंगलूर की छोड़कर अन्य सभी साधियों का मत था कि सीटू के साथी उन्हें उनके रोजमर्रा के कामकाज तथा महिला समिति के काम में मदद करते हैं।

हुबली के हैडलूम मजदूरों ने हैडलूम बुनकरों को धागा न देने की सरकारी नीति के कारण उत्पन्न सोचनीय स्थिति के बारे में बताया। बीड़ी मजदूरों को भी पत्तों की कमी के कारण काम मिलने में कठिनाई हो रही है। भविष्यनिधि की समस्या भी है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित फैसले किये गये :

1. आई.सी.डी.एस. मजदूरों को संगठित किया जाये। जहाँ आंगनवाड़ी की इकाइयाँ हैं वहाँ जिलावार सम्मेलन आयोजित करने के बाद अगस्त, 1993 तक एक राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाये।

2. आने वाले तीन माह में, सभी जिलों में (जहाँ तक संभव हो) कामगार महिला समन्वय समिति के जिला सम्मेलन आयोजित किये जायें तथा सीटू की मदद से समितियाँ स्थापित की जायें।

3. 9 सितम्बर के कार्यक्रम तथा 'जेल भरो' को गंभीरता से लिया जाये तथा उसे सफल बनाने के लिए काम किया जाये।

4. कपड़ा व अगरवती उद्योग की महिलाओं को संगठित करने के लिए काम किया जाये तथा इसकी रिपोर्ट उच्चतर समिति को दी जाये। इन फैसलों के साथ साथ 4 वजे बैठक समाप्त हुई।

कामगार महिलाओं के लिए 'कक्षा'

1979 में ए.आई.सी.सी.डी.डब्ल्यू. डब्ल्यू. की स्थापना के बाद से पहली बार सीटू व अन्य फेडरेशनों से जुड़ी कामगार महिलाओं के लिए कक्षा का आयोजन हैदराबाद में 23-25 जुलाई, 1993 को किया जा रहा है। युनियनों की लगभग 40 महिला नेताओं के इस कक्षा में शामिल होने व अध्ययन करने की संभावना है। आशा की जाती है कि वे बाद में स्थानीय भाषाओं में ऐसी कक्षाएं लेंगे।

कक्षा में भारत व अन्य देशों के राजनीतिक घटनाक्रम, कानूनी प्रावधानों, इतिहास, मजदूर आन्दोलन व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों आदि के बारे में बताया जाने की संभावना है।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि का. एम.के. पंथे, का. सुकोमल सेन, का. उमानाथ, का. श्री हरि तथा आई.एल.ओ. के एक प्रतिनिधि मंडल कक्षा में आने तथा विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए सहमत हो गये हैं।

कक्षा में भाग लेने वाले सदस्य एक दिन का अवकाश लेकर अपने आने व जाने की सूचना निम्नलिखित पते पर दे दें। वे अपने राज्यों से ही वापसी के टिकट भी बुक करा लें।

पता : महासचिव,

आंध्रप्रदेश राज्य समिति, सीटू,

1-1-60/4, इपितकार मेशन,

मुश्तिदाबाद,

हैदराबाद-500020

आंध्रप्रदेश

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

केरल के खादी वस्त्रोद्योग में महिलाएं केवल पांच से नौ रु. पा रही हैं—कामगार महिला समन्वय समिति

प्रसन्ना कुमारी

12-3-93 को नागपुर में हुई अखिल भारतीय बैठक में केरल राज्य के चार सदस्यों ने भाग लिया। राज्य समन्वय समिति की बैठक 7-4-92 को सीटू राज्य समिति के कार्यालय में हुई। बैठक में राज्य सीटू महासचिव का. के.एन. रवीन्द्रनाथ तथा सचिव का. के.ओ. हबीब, का. एम. पद्मालोचन, का. के. पद्मनाभन तथा का. बी. जे. के. नायर उपस्थित थे। का. एन.बी. प्रसन्नाकुमारी ने ऑल इंडिया कमेटी के फैसलों की जानकारी दी।

समन्वय समिति के काम-काज के बारे में गहन विचार-विमर्श हुआ। राज्य व जिला समितियों का काम-काज आशाओं के अनुरूप नहीं रहा। 55 सदस्यीय राज्य समिति में से 15 सदस्य बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। मध्यमवर्गीय कर्मचारी बैठकों में नियमित रूप से आये। केरल के 14 जिलों में से 13 जिलों में महिलाओं के सम्मेलन हुए तथा जिला समितियां गठित की गयीं लेकिन उनका काम-काज संतोषजनक नहीं रहा। कुछ मुद्दों को उठाया गया व उनको मनवाने में सफलता भी प्राप्त हुई। मध्यमवर्गीय यूनियनों की महिला उपसमितियां महिलाओं के मुद्दे उठाने में सक्रिय स्वरूप प्रदर्शित कर रही हैं। सभी जिला समितियों में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं लेकिन वे बैठकों में भाग लेने के लिए बहुत कम आते हैं। अतः समन्वय समिति के लिए उनके मुद्दे उठाना मुश्किल होता है। दरअसल उनकी अपनी समस्याएं व मांगें हैं। जैसा कि का. विमल रणदिवे की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीटू यूनियनों की ओर से पर्याप्त उसाह न दिखाये जाने के कारण महिलाओं को संगठित करने में बाधा आ रही है।

दूसरा कारण यह है कि यूनियनों को सदस्यों को आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए क्योंकि समन्वय समिति का अपना कोई फंड नहीं होता है। छोटी-छोटी यूनियनों को आर्थिक कार्यों से अपना काम-काज चलाने में बाधा का सामना करना पड़ता है। यदि समिति के

पास अपना फंड होगा तो उसे अपना काम-काज सुगमता से करने में आसानी होगी।

आंगनवाड़ी यूनियन को 'आइडवा' द्वारा संगठित किया गया व मजद दी गयी। 'आइडवा' की सचिव टी. देवी भी बैठक में मौजूद थीं। उन्होंने आंगनवाड़ी यूनियन की ताजा स्थिति की जानकारी दी।

का. रवीन्द्रनाथ ने समन्वय समिति को मजबूत बनाने की जानकारी दी।

पूरे विचार-विमर्श से समिति की कमजोरियां उभर कर आयी। यह फैसला किया गया कि विभिन्न तबकों की महिलाओं को संगठित किया जाये तथा उन्हें यूनियन के कामकाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। कामगार महिला समन्वय समिति तथा 'आइडवा' की मदद से सीटू को आंगनवाड़ी यूनियनों की सहायता करनी चाहिये। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने का भी फैसला किया।

इस बैठक के बाद सीटू के पदाधिकारियों ने 29-8-92 को बैठक की व यूनियन की अन्य समस्याओं पर विचार किया। सभी यूनियनों तथा सीटू की जिला समितियों को इसकी सूचना दी गयी लेकिन अनेक यूनियनों ने बैठक में भाग नहीं लिया।

खादी वस्त्रोद्योग में महिलाओं की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। खादी और ग्रामोद्योग में लगभग 42 लाख मजदूर कार्यरत हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। केरल में लगभग 26 हजार महिलाएं खादी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन महिलाओं को प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक काम करना पड़ता है तथा उन्हें केवल 5 से 9 रु. तक मिलते हैं। खादी बोर्ड एक राष्ट्रीय मूल्य सारणी के आधार पर वेतन निर्धारित करता है। वेतन वेतन के लिए राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाये जाने चाहिए व आंदोलन किये जाने चाहिए। उन्होंने अपील की कि राष्ट्रीय समिति बनाने के लिए उन्हें मदद करनी

चाहिए।

अल्प यूनियनों के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

हलांकि बैठक पूरी तरह से सफल नहीं रही लेकिन इससे अनेक समस्याओं की समझने में मदद मिली। यह फैसला किया गया कि अधिक-से-अधिक यूनियनों की भागेदारी बढ़ाने के लिए सीटू की जिला स्तरीय बैठकें बुलाने की मांग की गयी। उस विषय पर आगे कोई प्रयास नहीं किया गया।

आंगनवाड़ी

सीटू की पहल पर 13-9-92 को त्रिवेन्द्रम में आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भागेदारी अच्छी नहीं रही।

अखिल भारतीय संगठन तथा संघर्ष समिति के गठन से कुछ लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है। लेकिन और यूनियनों के बन जाने से तथा हमारी ओर कँठर कम होने के कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। का. के.एम. कमलम्मा को सीटू की ओर से आंगनवाड़ी का जिम्मा सौंपा गया है। जिला सीटू समितियाँ व कामगार महिला समितियाँ उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रही हैं। कुछ जिलों में सम्मेलन आयोजित किये गये। हम संयुक्त संघर्ष समिति के संघर्ष का प्रचार कर सकते थे। जिसके परिणामस्वरूप मानदेय में वृद्धि करवाई जा सकती थी। कसारगोड़ जिले में एक अच्छा सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ा हुआ मानदेय प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रचार

समिति को मजबूती प्रदान करने के अलावा हमने देश में मौजूद सांप्रदायिकता के खतरे पर भी विचार किया। 30-9-92 को प्रायोजक समिति सांप्रदायिकता पर आयोजित सम्मेलन में विभिन्न तबकों की महिलाओं ने भाग लिया। 6 दिसम्बर को बावरी मस्जिद उद्घाटित करने का केरल में भी प्रभाव पड़ा। कुछ इलाकों में सांप्रदायिक टकराव हुए। अनेक लोग सांप्रदायिक जुनून का शिकार बने। महिलाओं व बच्चों को भी नहीं बचता

गया। प्रायोजक समिति के साथ ही साथ महिलाओं ने भी हिंसा के शिकार लोगों की मदद करने व एकता स्थापना करने के लिए पहल की। महिलाओं की विभिन्न लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं का समन्वय करते हुए एक संयुक्त महिला समिति बनाई गयी। इस समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न तबकों की महिलाओं ने भाग लिया। महिला उद्यमियों ने कार्यस्थल में ली गई धर्मनिरपेक्षता की शपथ में भाग लिया।

राज्य समन्वय समिति की इस माह की 12 तारीख को बैठक हुई व उसमें सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने का फैसला किया

आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रचार

सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्षों में महिलाओं की भागेदारी बढ़ रही है। 16 जून की हड़ताल में महिलाओं की भागेदारी संपूर्ण रही। लेकिन महिलाओं के बीच प्रचार का काम प्रभावशाली नहीं रहा। 25 नवंबर के कार्यक्रम के पहले बेहतर प्रचार अभियान चलाया गया तथा उसके परिणामस्वरूप महिलाओं की भागेदारी भी बेहतर रही।

टाक व तार विभाग के कर्मचारियों ने श्रमिक संघ कक्षा का आयोजन किया। इसमें लगभग सभी सदस्यों ने भाग लिया। गैर सरकारी संगठनों व अध्यापकों ने प्रचार अभियान में सक्रिय भागेदारी की। फिरहाल हड़ताल को मुलतबी कर दिया गया है।

राज्य बिद्युत बोर्ड की कामगार महिला समिति में महिला अधिकारी शामिल हैं। समिति की 9 फरवरी को बैठक हुई तथा उसमें सांप्रदायिकता व सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रचार अभियान जारी रखने का फैसला किया गया।

कसारगोड़ जिला समिति ने मजदूरों की बैठक आयोजित की जब का. चिमल रणविवे नर्सों के सम्मेलन का उद्घाटन करने आयी थीं।

श्रम संगठनों की गतिविधियों के अलावा महिला समितियाँ सामाजिक कार्यों में रूचि ले रही हैं। हमारी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे क्रेष व छात्रावास अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अब हमने कसारगोड़ जिले

[शेष पृष्ठ 20 पर]

नयी आर्थिक नीति और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स

राजम्मा

भारत इलैक्ट्रॉनिक्स, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हम राडार, ई.सी.जी व अन्य उपकरण बनाते हैं जिन्हें आर्मी, नौवी तथा पुलिस बल खरीदते हैं। हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे टी.वी. पिक्चर ट्यूब, कैपेसिटर्स आदि भी बनाते हैं हैं। सरकार तथा सुरक्षा बल हमारे नियमित ग्राहक रहे हैं तथा हम उनसे अच्छा मुनाफा कमाते रहे हैं।

इस उपक्रम में लगभग 18,000 कर्मचारी कार्यरत थे तथा उनमें से 5000 महिलाएं थीं। अपने पूरे इतिहास में बी.ई.एल. ने कभी घाटा नहीं उठाया तथा पूरे भारत भर में उसकी सात शाखाएं खुल गयीं।

अब यह अतीत की बात हो गयी है। सरकार की नयी नीतियों के कारण बी.ई.एल. में भी स्थितियां बदल रही हैं। पहले उन्होंने कम समय में अधिक काम करवाने के नाम पर ऑफ लोडिंग शुरू की तथा फिर उत्पादन लागत में कमी के नाम पर श्रम शक्ति घटाई। इसके पीछे तर्क यह था कि उप ठेका प्रणाली से उत्पादन लागत घटेगी तथा लाभ बढ़ेगा। लेकिन बाद में यह उप-ठेका प्रणाली इतनी बड़ी कि उच्च अधिकारी व कुशल कर्मचारी भी ठेकेदारी के माध्यम से घन कमाने के लिए नौकरी छोड़ने लगे।

इस प्रक्रिया में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन प्रभावित हुई। एक मामले में ऐसा हुआ कि कुछ काम बाहर से करवाया गया तथा बाद में वही कंपोनेंट प्रबंधकों ने पुनः खरीदे। इस कार्य को ठेके पर करवाने तथा बाद में उन्हीं वस्तुओं को खरीदने की तथा आवश्यकता थी। बाद में वह विभाग बन्द कर दिया गया तथा मजदूरों को विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया गया।

टी.बी. पिक्चर ट्यूब निर्माण विभाग में पहले हम ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूब बनाते थे। अब ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूब की मांग नहीं है। हालांकि हमारे पास रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने की क्षमता है लेकिन हमें रंगीन

पिक्चर ट्यूब बनाने का लाइसेंस नहीं मिला है। अनेक प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। अनेक बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के टी.वी बाजार पर कब्जा कर लिया है। इस नीति को अपना कर टी.वी. ट्यूब के विभाग को बन्द कर दिया गया है। इस औद्योगिक प्रतिष्ठान की वर्तमान दशा दयनीय है। किसी दोष दिया जाये।

हमारी सीटू यूनियन ने यह मामला उठाया है तथा भारत सरकार के इस रवैये पर कई दफा हमारा विरोध प्रकट किया है। भारत सरकार अपने अनिवेश तथा विश्व-बाजार से प्रतिस्पर्धा अपने कार्यक्रम पर निरंतर चलती जा रही है।

वर्तमान स्थिति यह है कि प्रबंधक कार्यरत कर्मचारियों को भी काम देने के इच्छुक नहीं हैं। हर जगह कर्मचारी अपनी सीट पर आराम कर रहे हैं और प्रबंधक उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या 18 हजार से घट कर 8 हजार हो गयी है। तथा उनके लिए भी पर्याप्त काम नहीं है। यह किसका दोष है। हर मजदूर के विभाग में उद्योग बन्द होने, निजीकरण या बीमार घोषित किये जाने का डर समाया है तथा वे मदद के लिए श्रम संगठनों की ओर देख रहे हैं।

[पृष्ठ 19 का दोष]

भी एक केच आरंभ करने का फैसला किया है इससे बीड़ी मजदूरों के बच्चों को लाभ होगा।

सीटू राज्य समिति कामगार महिला समन्वय समिति की ओर अधिक ध्यान दे रही है। हमें आशा है कि संयुक्त प्रयासों के द्वारा हम महिला उद्यमियों के वर्ग में अधिक प्रगति कर सकते हैं।

राज्य सभा याचिका समिति ने 10.2.93 को कोचीन का दौरा किया। इसके अध्यक्ष सुन्दर सिंह भंडारी थे तथा इसमें मीरा दास व अन्य लोग शामिल थे। कामगार महिला समन्वय समिति ने उन्हें विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं की जानकारी दी।

सेविकाओं-सहायिकाओं द्वारा बाल विकास परियोजना

कार्यालय नौबतपुर पर धरना

12 मार्च '93 को बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ की प्रखंड शाखा नौबतपुर की सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बाल विकास परियोजना कार्यालय (नगवा) नौबतपुर के समक्ष धरना का कार्यक्रम राज्य संघ के निर्णयानुसार आयोजित किया गया। बिहार राज्य के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना/प्रदर्शन आयोजित कर सरकार एवं परियोजना पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु किया जा रहा है।

नौबतपुर बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आयोजित इस धरना-कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इस प्रखंड के सुदूर गाँवों की आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपने संघ के बैनर के साथ परियोजना कार्यालय पर धरना कार्यक्रम में भाग लेने भारी संख्या में इकट्ठा हुयीं और संघ की ओर से साथी रीता विश्वकर्मा ने माँग-पत्र की मांगों धरना स्थल पर पढ़कर सुनाया तथा सेविकाओं-सहायिकाओं ने अपनी माँगों के समर्थन में नारे लगाये।

2 बजे अपराह्न में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर से एक शिष्टमंडल संघ की ओर से मिला और माँग-पत्र प्रस्तुत किया। माँग-पत्र के स्थानीय माँगों को उनके द्वारा पूरा किये जाने का आश्वासन दिया और राज्य सरकार से संबंधित माँगों को सरकार के पास भेजने का वचन दिया गया। सेविकाओं-सहायिकाओं के बकाये मानदेय का भुगतान अप्रैल '93 के प्रथम सप्ताह तक कर देने का भी आश्वासन दिया गया।

उसके बाद धरना-स्थल पर एक सभा भी हुई जिसे स्थानीय श्रमिक नेता का. इन्द्रदेव प्रसाद सिन्हा (माकपा) ने संबोधित किया और कहा कि परियोजना पदाधिकारी तथा राज्य सरकार सेविकाओं तथा सहायिकाओं की माँगों को पूरा करने की दिशा में अविलंब कदम उठाये तथा बेतावनी दी कि अगर इन माँगों को पूरा नहीं किया

गया तो राज्य के पैमाने पर व्यापक आंदोलन छोड़ दिया जायेगा। श्रमिक नेता ने केन्द्र सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए इसे मजदूर विरोधी बतलाया तथा सरकार से इसे वापस लेने की माँग की। अन्त में संघ की ओर से परियोजना पदाधिकारी को बेतावनी दी गयी कि अगर आश्वासन के अनुरूप माँगों की पूर्ति नहीं की गयी तो परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया जायेगा जिसकी सारी जबाबदेही पदाधिकारी महोदय की होगी।

अन्त में संघ की प्रखण्ड शाखा की अध्यक्षों साथी मालती कुमारी के धन्यवाद जापन के बाद धरना का कार्यक्रम समाप्त किया गया।

महोदय,

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ की प्रखंड शाखा नौबतपुर के द्वारा आज दिनांक 12-3-93 को बाल विकास परियोजना कार्यालय नगवा (नौबतपुर) के समक्ष धरना कार्यक्रम के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते करते हुए निम्नलिखित माँगों की शीघ्र पूर्ति हेतु आपसे माँग की जाती है—

1. इस परियोजना में कार्यरत सहायिकाओं एवं सेविकाओं के बकाये मानदेय का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करायी जाये।

2. समय पर पोषाहार की आपूर्ति की जाए तथा सभी केन्द्रों के लिए समान अनुपात में पोषाहार की आपूर्ति की जाये तथा लिखित सूचना के आधार पर पंचायतवार ढंग से इसका वितरण कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

3. इस परियोजना की बंसी सेविकाओं तथा सहायिकाओं को जिनका अपने कार्य क्षेत्र में कार्य सम्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है के आधार पर सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।

4. सेविकाओं के जलावन का विपत्त, डुलाई भाड़ा तथा मकान किराया का भुगतान कार्यालय द्वारा यथा-

शीघ्र सुनिश्चित करवाया जाये।

5. किसी भी केन्द्र को अकारण बंद नहीं रखा जाये तथा सेविकाओं एवं सहायिकाओं का अकारण न्यून रह नहीं किया जाये तथा स्पष्टीकरण देने का समुचित सु-अवसर प्रदान किया जाये।

6. इस परियोजना में भी अन्य परियोजनाओं की तरह बाल पोषाहार के रूप में माँडने फूड की आपूर्ति बंद कर बाबल-दाल तथा हरी सब्जी की व्यवस्था करायी जाये।

7. संघ को इस परियोजना में कार्यरत सेविकाओं तथा सहायिकाओं की सूची अविलंब उपलब्ध करवाई जाये।

8. सेविकाओं एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी अविलंब घोषित किया जाये।

9. तत्काल सेविकाओं के लिए 600 रु. माहवार तथा सहायिकाओं के लिए 400 रु. मानदेय लागू किया गया जाये।

10. महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर सेविकाओं को बहाल किया जाये।

11. सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप सेविकाओं को छुट्टियाँ प्रदान की जाये।

मई दिवस पर विश्व भर में महिलाओं का क्रांतिकारी अभिनन्दन

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू. विश्व भर की महिलाओं का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है जो जन-साधारण की मुक्ति तथा पूँजीवादी-साम्राज्यवादी शासन के त्वात्मे के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम इस अवसर पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में संघर्षरत अपनी महिला साथियों का अभिनन्दन करते हैं जो जन-जीवन का क्षरण करने वाली नयी बाजार व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश प्रदर्शनों व हड़तालों के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। ए.आई.सी.सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. समाजवाद की स्थापना के लिए उनके संघर्ष का समर्थन करती है। हम चीन विद्यतनाम, उत्तरी कोरिया व क्यूबा की महिलाओं का अर्थव्यवस्था में शानदार प्रगति के लिए अभिनन्दन करते हैं। पूँजीवाद व साम्राज्यवाद के अन्तर्गत रह रही महिलाओं की मुक्ति हासिल करने के लिए अभी बहुत लम्बा सफर करना होगा। हम विश्व की सभी संघर्षरत महिलाओं के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं। समाजवाद अमर रहे।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू ने एकजुटता प्रकट की

कों. बायो क्वेकी

निदेशक,

विदेश विभाग

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस,

51, प्लेन स्ट्रीट,

पी.ओ. बॉक्स 61884,

जोहान्सबर्ग,

दक्षिण अफ्रीका।

प्रिय महोदय,

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता तथा दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कों. क्रिस हानी की रंगभेदी शासन के एजेंटों द्वारा की गयी जघन्य हत्या पर गहरा दुःख व शोक व्यक्त करती है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टफ मुक्ति संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में रहे। रंगभेद के उनके पुरजोर विरोध से लाखों लोगों के मन में शांति व सहयोग तथा रंगभेद के अन्त की उम्मीद जगी थी तथा शासन उनको रास्ते से हटाने की लगातार साजिश कर रहा था।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू. इस हत्याकांड की भर्त्सना करने में विश्वमत के साथ है।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. कों. क्रिस हानी को अदालत अर्पित करती है तथा उनके परिवारजनों व दक्षिण अफ्रीकी जनता के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है।

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू (सीट) स्वतंत्र, भेद-भाव रहित तथा लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीकी जनता के प्रति पूरी एकजुटता प्रकट करती है।

क्रांतिकारी अभिवादन सहित,

बिमल रणदिवे

(सचिव)

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति

कामकाजी महिला

जून, 1993

आंगनवाड़ी महिलाएं भारत बन्द में शामिल होगी

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन की कार्य-समिति की बैठक 19 जून '93 को 14 अशोक रोड, अशोक रोड, नई दिल्ली में हुई। दस राज्यों से निम्न-लिखित साथी बैठक में मौजूद थे। का. के. हेमलता (आंध्रप्रदेश), राजचिन्दर कौर (पंजाब), का. निर्मल कान्त (पंजाब), सुरिन्दर पंजाब), का. निर्मल सिंह गिल (पंजाब), का. आर. आनन्दराजन (पांडिचेरी), का. ब्रज गोपाल नेगी (प. बंगाल), का. बान्तोप राय (पश्चिम), बंगाल), का. मान्यता सरोज (खालियर, म.प्र.), का. पलानी नाथन (तमिलनाडु), का. के. सुब्रमण्य (तमिलनाडु), का. सरोज वशिष्ठ (हरियाणा), का. किरण मोघे (महाराष्ट्र), का. उमा सरीन (जयपुर) तथा सुसीला सरीन (जयपुर)।

शहीदों पर प्रस्ताव रखते हुए का. विमल रणदिवे ने बैठक की शुरुआत की। रैड बैंक गार्डन, बनारस में हुई घटना की भर्त्सना की गयी जिसके 13 आंगन मजदूर शिकार बने। सदस्यों ने उन साथियों की याद में दो मिनट का मौन रखा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में का. विमल रणदिवे मान-देय में वृद्धि होने के बाद संगठन में आयी कमजोरियों के बारे में बोलीं। हमारा उद्देश्य सेवाकार्यों व सहायिकाओं के लिए 800-400 रु. मानदेय प्राप्त करना था। अभी भी बिहार जैसे अनेक राज्यों में स्थितियाँ बेहद खराब हैं। पंजाब में कुछ महिला मजदूर कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस महिला विंग में शामिल हो गयीं। लेकिन आम मजदूर इस नेतृत्व के साथ नहीं गया। उन्होंने आमसभा में नयी समिति का चुनाव किया तथा बैठक में शामिल हुई। तत्पश्चात, का. नीलमा रॉय (महासचिव) ने काम की रिपोर्ट रखी तथा उपलब्धियों व संघर्ष के बारे में बताया। पांडिचेरी में महिलाओं को लम्बे संघर्ष के बाद 800 रु. वोनस प्राप्त हुआ। यह बढ़ा हुआ मानदेय भी हमारी राज्य समिति व संयुक्त संघर्ष समिति के लम्बे

संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे बैठक में उपस्थित हों तथा संबद्धता शुल्क नियमित रूप से भेजें। का. बान्तोप राय ने भी संगठन की मजबूत बनाने की अपील की।

अधिकतर राज्यों की प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। (वित्त रिपोर्ट अगले अंक में प्रकाशित की जायेगी। निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम भविष्य के लिए निर्धारित किये गये।

1. 19 अगस्त को भारत बन्द के अवसर पर गिरफ्तारी के कार्यक्रम में पूर्णरूप से भाग लिया जाये।
2. 12 जुलाई को सारे देश में सभी परियोजनाओं में मांग दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

त्रिची में सम्मेलन

12 जून को हमने कामगार महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया। हम एक सप्ताह पहले से ही इसका प्रचार करने के लिए 'भैल' बीडिक, सिक्को, म्युनिसिपल इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, ई.सी.बी. बैंक एंड नाडार फैंक्ट्री, आदि स्थानों पर गये। पहली बार हमारा अनुभव अच्छा रहा तथा सभी ने कहा कि वे आएंगे। दरअसल हमने सोचा था कि इस बार भी पिछले दो वर्षों की तरह होगा कि कोई नहीं आयेगा। लेकिन इस बार का अनुभव ऐसा नहीं था क्योंकि 12 तारीख को लगभग 50 महिलाएं आयीं और उनमें से सात अपनी समस्याओं के बारे में बोलीं। हमने एक तरह सदस्यीय समिति का चुनाव किया जिसकी संयोजक का. ऐलेन शंभुगम तथा हण्णा बाई होंगी। बैठक में दो प्रस्ताव पास किये गये एक हमारे इलाके के समस्याओं के बारे में तथा दूसरा 13 जुलाई के घरने के बारे में।

[पृष्ठ 2 का शेष]

संयुक्त संघर्ष समिति के बारे में भी दो शब्द कहे जिसने आंगनवाड़ी महिलाओं के मामले को उठाया था।

उन्होंने अलगवावाद के विरुद्ध लड़ने तथा सामुदायिक समता के लिए मजबूत संगठन की अत्यन्त आवश्यकता का उल्लेख किया। जिसके बिना संगठित आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने केन्द्र सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों पर आरोप लगाया। यह आधिक नितियाँ निश्चय ही कामकाजी महिलाओं पर प्रभाव डालेंगी। बैठक का सम्बोधन कामकाजी महिला को कमेटी, पंजाब की सचिव द्वारा भी हुआ।

बाद में जनरल बॉडी में 21 सदस्यीय पैनल पारित किया गया जिसमें रजिस्ट्रार को प्रधान तथा निर्मल कान्ता को सचिव रूप में चुना गया।

हमारे चण्डीगढ़ संवाददाता ने लिखा कि बैठक के बाद कार्य शुरू हो गया। सभा में आंगनवाड़ी बोर्ड के विकास से संबंधित विधान की 2000 प्रतिमा पारित की गई तथा सदस्यता नामांकन के 10,000 फार्म तुरन्त छापकर जिलों को भेजे गये। सदस्यता हेतु प्रचार बहुत तेजी से किया जा रहा है। ब्लाक चुनाव भी होने जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि हम 30 जून तक 62 ब्लाकों में से 39 ब्लाकों में सफलता पूर्वक चुनाव करवा देंगे। 17 मई की हमारे कार्यालय कार्यकर्ताओं का दस सदसीय शिष्ट मंडल समाज कल्याण विभाग के निदेशक तथा सचिव से मिला और उन्होंने मांग पत्र पेश किया। निदेशक ने हमारे संघ के साथ 10.6.93 को बैठक तय कर दी है। इस बैठक तथा सदस्यता प्रचार के परिणाम बैठक के बाद आपके पास भेज दिए जायेंगे। 19.6.93 को दिल्ली में होने वाली आल इंडिया फंडेशन की बैठक में प्रधान तथा महासचिव भी हिस्सा लेंगे।

यह मास अफवाह ही बन कर रह गई कि सुरिन्द्र कौर भी 5.6.93 को आलन्धर में ऐसी ही सभा करने जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 23.5.93 को बैठक भी आयोजित की थी। परन्तु यह बैठक बुरी तरह असफल रही। पुराने नेताओं में से रजबत (गुरुदास पुर) ही उपस्थित थे। फिर भी इसमें 6-7 नए चेहरे भी थे।

उन्होंने सभा आयोजित करने का विचार छोड़ दिया परन्तु 10.6.93 को निदेशक के कार्यालय में समान शिष्ट मंडल से जाने का निश्चय किया ताकि वहाँ कुछ हरकत की जा सके। परन्तु हमारे सभी पी.एस.एस.एफ. कामरेड सतर्क हैं और हमें विश्वास है कि हम उनकी इस योजना को दुबारा असफल साबित करेंगे।

[पृष्ठ 13 का शेष]

आरक्षित स्थान 24 हजार के लगभग हैं। परन्तु कई बार महिलाओं ने सामान्य सीटों के लिए भी चुनाव लड़ा है। वास्तव में गांवों में यह मुँह का खोत बनकर सामने आया है। 15 वर्ष बाद पंचायत व्यवस्था को आधारभूत प्रगति के लिए स्थिर और व्यवहार्य रूप में परिवर्तित किया गया है। इस स्थिति में औरतों की विशाल भागीदारी इसे अतिरिक्त गति प्रदान करेगी चुनाव प्रचार में औरतों की विशाल एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता के बिना पहले से ही मौजूद हैं।

उपरोक्त साधारण किसान जन-जातीय महिलाओं की जीवन यात्रा पढ़ने के बाद भी क्या हम हैरान होंगे कि कांग्रेस (आई) तथा भाजपा के हाथ मिलाने पर भी पंचायत चुनाव के बड़े परिणाम क्यों आए ?